>

Title: Need to provide a special financial package to Chhattisgarh to give impetus to development in the State.

**कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग):** वर्ष 2000 में देश में तीन नए राज्यों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, और झारखण्ड। जब भी नए राज्य का गठन होता है तो प्रशासनिक एवं सभी आवश्यक संस्थाओं के गठन एवं स्थापना में धन लगता है, क्योंकि राज्य भी नया होता है। इसलिए राजस्व की प्राप्ति भी समुचित नहीं रहती। इस हेतु केन्द्र द्वारा कई राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज भी जारी किया जाता है। किंतु यह विडम्बना है कि इन राज्यों के गठन के पश्चात् सिर्फ उत्तराखण्ड को ही आर्थिक पैकेज दिया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम उस प्रदेश में दिखाई भी पड़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं किंतु उसके लिए केवल संसाधन ही नहीं आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की लगभग 46 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित और पहाड़ी है। खनिज भी इन्हीं वनों के नीचे है जिससे इनका दोहन लगभग असंभव हो जाता है। राज्य का औद्योगिक विकास मुख्यतः कोर सेक्टर अर्थात् स्टील, ऊर्जा, सीमेंट तथा एल्युमीनियम क्षेत्र में बना है। उपभोक्ता क्षेत्र, केमिकल, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लग पाए है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है तथा समुद्री किनारों और बंदरगाहों से भी काफी दूर है जिससे इसके तेजी से औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी काफी क्षीण हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ राज्य को भी केन्द्र विशेष आर्थिक पैकेज दे जिससे इस राज्य में भी अन्य प्रकार के उद्योग लग सके। इससे न सिर्फ इस राज्य के लघु और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे। अतः यह उचित होगा कि जल्द से जल्द केन्द्र इस बाबत निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ को विशेष पैकेज प्रदान करें।